सीमा-शुल्क आयकर विभागो आदि के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

2465. **श्रीमती वीणा वर्मा :**

श्री राम चन्द्र विकल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मंत्रालय ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, आयकर विभागो और प्रवर्त्तन निदेशालय के उन कर्मचारियो को जो वित्तीय अनियमितताओ का पता लगाने मे लगे हुए हैं इनाम देने की कोई प्रोत्साहन योजना लागू की है, और

(ख) यदि हा तो उपयुक्त अवधि के दौरान उस योजना के अधीन दिये गये पुरस्कारो का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हा ।

(ख) आय कर प्राधिकारियों ने 743 मामलो मे पुरस्कार प्रदान किये तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण तथा नार कोटिक प्राधिकारियो ने 7321 मामलो मे पुरस्कार प्रदान किये । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भी 814 मामलो मे पुरस्कार दिए गए थे ।

Smuggling of Synthetic Textiles

2466. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large scale smuggling of synthetic textiles has adversely affected the power-loom and mill sectors of the textile industry;

(b) what were the wholesale prices of smuggled Boski 45 variety, suiting 54 and sarees and the prices of comparable Indian varieties; and

(c) whether his Ministry has recommended to the Ministry of Finance to reconsider its excise policy in regard to PFY and other raw materials used in the production of synthetic textiles, and if so, what is the response thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) While Government are aware that there is some smuggling of synthetic textiles, it is not possible to give precise figures of the quantum of prices of smuggled goods.

(b) The price, of Indian varieties of cloth are given in the statement attached. (*See* below)

(c) The Textile Policy in June, 1985, states that fiscal levies on man-made fibres/yarn and on intermediates used as inputs for the production of such fibres/yarn shall be progressively reduced in such a manner as to facilitate absorption of increased domestic production, so that the benefit flows to the consumer in the form of lower prices of synthetic and blended fabrics. However, details of specific proposals regarding changes in excise duties sent to the Finance Ministry are not disclosed before a final decision is taken thereon.

Statement

Ex-Mill prices of Mill-made Fabrics as on September 1987

	(Rs. per mtr.)
1. Suitings (132—137 cms.) (avg. of 7 verieties)	50.38
2. Shirtings (89—91 cms.) Poplins. (avg. of 9 varieties)	22 00
3. Sarees (Avg. of 6 varieties)	24 60

Month End Market Prices of Filament Fabrics

(Rs. per mtr.)

	September, 1987
Texo Bosky 47"	
76x76 (5 5 kgs.) printed	14 10
Dyed	15 00
China Bosky	
44x76 (5.5 kgs.)	12 00
44x76 (7 0 kgs.)	15.00
Saree Cloth (49")	
60s (67/33)x76D Texturised 88x76	10.65

Loans for setting up industries

2467 DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of loans sanctioned by the Central Government to industrialists for setting up industries and factories during the last three years, State-wise, and the amounts sanctioned;

(b) the number of industries and factories set up by them during this period;

(c) the amount towards loan repaid by the loanees, State-wise, till October 1987; and

(d) the steps taken by Government to recover the loans from those who have failed to repay the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House to the extent available and permissible under the rules.

ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के कतिपय विभागों में काम का बन्द होना

2468. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री अजीत जोगी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर स्थित जियाजी काटन मिल्स के प्रबंधकों ने मिल के कुछ विभागों मे काम बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या मे मजदूर कार्यमुक्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हा, तो ऐसे मजदूरो की संख्या कितनी है और उन्हे वैकल्पिक रोजगार देने के सबध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जियाजी काटन मिल्स लि०ग्वालियर ने मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसा आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे 414 पुराने ताने करघो और अनुषगी विभागों के कार्य चालन को निलम्बित करने के लिये औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अधीन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है । मध्य प्रदेश सरकार ने इस आवेदन-पत्र का निपटान करते हुए मिल के प्रबन्ध-मण्डल को निर्देश दिये कि प्रभावित कामगारों के लिये एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना तैयार की जाये । स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना क्रियान्वित हो रही है । किसी भी कामगार को जबरन बेरोजगार नही किया गया है ।